



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 110]
No. 110]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1984/श्रावण 27, 1906
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1984/SRAVANA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय
(आयात व्यापार विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पीएन)/84

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1984

विषय:—1984-85 के लिए 20 मिलियन (20,000) येन की जापानी
अनुदान सहायता के अंतर्गत नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम
द्वारा जापान से भारत में परतों तक उप-
करण ले जाने के लिए आवश्यक शोध विज्ञान उपकरण और
सेवाओं के आयात के लिए लाइसेंस की शर्तें।

मिनिस्त्र सं० आईटीसी/23(6)/84:—जापानी अनुदान सहायता 20
मिलियन येन के अंतर्गत नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम द्वारा
शोध विज्ञान उपकरण के आयात के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के
लिए लागू जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, उन्हें
जागरूकता के लिए प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाशक: नवीन, मुख्य निबंधक: आयात एवं निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पीएन)/84
दिनांक 18-8-1984 से लिए परिशिष्ट

1984-85 के लिए 20 मिलियन (20,000) येन की जापानी अनुदान
सहायता के अंतर्गत जापान से भारत में शोध विज्ञान उपकरण और

सेवाओं की भारत में परतों तक ले जाने के लिए आवश्यक सेवाओं के
आयात के लिए लाइसेंस की शर्तें।

खण्ड-I, सामान्य शर्तें:—

1(1) 1984-85 के लिए 20 मिलियन येन (लागत और भाड़ा)
की जापानी अनुदान सहायता का उद्देश्य शोध विज्ञान उपकरण और
सेवाओं के आयात के लिए जापानी संघर्षों की भुगतान करने के लिए और
भारत में नेशनल काउंसिल आफ साइंस आफ म्यूजियम, कलकत्ता द्वारा
भारत के परतों पर उनको लाने के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग
करना है।

1(2) आयातक के नाम के आयात लाइसेंस "कुल मिलाकर 22 मिलियन
येन (लगभग बीस लाख) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं किए जाने
वाले हैं और उन पर एक सील "1984-85 के लिए 20 मिलियन येन
जापानी अनुदान सहायता" होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्येक के
लिए लाइसेंस संकेत "ए/जे एन" होगा।

1(3) बैंक आफ इंडिया, टोकियो की बैंक-बर्च, जिनका लेखा सहाय्य
बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के प्रतिरिक्त विदेशी मुद्रा
यदि कोई हो, के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं
दी जाएगी। भारतीय अधिकारता के कमीशन के प्रति यदि कोई हो तो कोई
भी भुगतान अधिकारता की भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे
भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही
प्रसारित किए जाएंगे।

1(4) इस अनुदान सहायता के अधीन सामान केवल जापान से प्राप्त किया जाना चाहिए।

1(5) आयात लाइसेंस 31-3-1985 तक की अवधि के साथ लागत बीमा भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा।

1(6) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलवान वस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें सुपुर्दगी की अवधि के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए:—

“सुपुर्दगी 15-3-1985 तक पूर्ण की जानी है”

1(7) संविदा का मूल्य (केवल लागत तथा भाड़ा आधार पर) येन में दर्शाया जाना चाहिए (येन के भिन्न को हटाया जाना चाहिए) और यदि कोई हो तो भारतीय अधिकारों का कमोशन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रुपए या अन्य किसी मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए।

जहाज पर्यन्त निशुल्क लागत बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रवर्धित की जा सकती है, परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्च वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निविष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के प्रतिरिक्त देय धनराशि होगी।

1(8) न्य संविदा केवल जापानी राष्ट्रिकों अथवा जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित जापानी न्यायिक व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए।

खंड-2—संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए:—

2(1) 1984-85 के लिए 20 मिलियन येन की अनुदान सहायता से सम्बद्ध इस संविदा की व्यवस्था 11 मई, 1984 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है और यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस “भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र” (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1984-85 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम से सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

2(3) जापानी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और द्वारी और जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

2(4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलवान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए संबंधित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम की भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए छः सप्ताह पहले ही भारतीय दूतावास, टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए। विशेष मामलों में, जहाँ भारतीय आयातक यह चाहता हो, अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है। आवश्यक व्योरे देते हुए प्रत्येक पोतलवान के बाव जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन

3(1) जैसे ही आवेशों को अंतिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आवेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आवेश की चार प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-1 के प्रथम में “ए/ओ

जारी करने के आवेदन” की 2 प्रतियों सहित प्रवर सचिव (ए/ए) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजी जाएगी। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय वस्तु या उसकी कीमत के आधार पर आयोगों से उत्पन्न सभी संविदा संगणकों के लिए भी लागू होगी।

3(2) वित्त मंत्रालय (डीईए) जापान अनुभाग 1984-85 के लिए 20 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तज्ञान देने के लिए संविदा की एक प्रति जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का ए००००००० लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास, टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक का जापान अनुभाग उसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संभव मार्ग, नई दिल्ली-110001 को देगा जो कि जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो के अनुबंध 2 के अनुसार एक “भुगतान प्राधिकार पत्र” (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियां भारत का दूतावास टोकियो आयातक भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाव बैंक आफ इंडिया, टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रण को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

3(5) पोतलवान करने के बाव जापानी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को जापानी संभरक को अपने बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6) जापानी संभरक, को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को वेय बैंक खर्च भारत सरकार के लेखे को प्रमाणित किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक से सम्बद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को धन परेषित करके निर्गमित किया जाएगा।

खंड-4 खपता जमा करने का उत्तरदायित्व

4(1) मूल विनियम पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा भारत में आयातक से सम्बद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को अनुबंध 1 के (प) में उल्लिखित है, की शाखा होगी। उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनियम सेट केवल हम बात का सुनिश्चय कर लेने के बाव ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन धनराशि के बराबर खपता अन्य मामलों में जहाँ देते योग्य है ब्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धन राशि पर जापानी संभरक का बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा भुगतान को त्रिभि से वास्तविक दरमा जमा करने की तिथि तक को अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 10-8-83 के अनुसार सरकारी लेखे में जमाकर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन जापानी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकार/लेखे में खपता जमा किया जाता है के लिए देय है। वेबिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-78 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन धनराशि के बराबर खपत की गणना करने के लिए अपनाई जाने

बाली विनियम वर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय मिश्रित वर होगी या वह वर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इन संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व संबंध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले वेध धनराशि सरकारी लेखों में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकों से दस्तावेज लेने से पहले ही वेध धनराशि लेखों में सही रूप से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चय करने की आयातक की जिम्मेदारी होगी कि वेध धनराशि सरकारी लेखों में ठीक से जमा करवा दी गई है जब कि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में सीमा पुनः प्राधिकारियों से माल की सुपुर्गी प्राप्त की हो। उस मामले में जब आयातक सरकार को वेध धनराशि मान लूझाने से पूर्व जमा करवाने में असमर्थ होता है तो उसे आगे एल ए एस जारी करना रोक दिया जाएगा और मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात को तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा जिससे ऐसे आयातक को आगे कोई आयात लाइसेंस न जारी किया जाए। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट एण्ड एडवांसिज—843 सिविल डिपोजिटस—डिपोजिट फोर परचेजिंग एटसट्रा एण्ड परचेजिंग प्रन्डर ग्रान्ट ऐड फाम गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1984-85 ग्रान्ट फार परचेज आफ रेडियो विजियु-अल इक्विपमेंट/सर्विसेज फार वि परचेज आफ ट्रेनिंग वि एक्सटेंस आफ दि नेशनल काउंसिल आफ साइंस म्यूजियम कलकत्ता।

4(2) नालान के बाएँ कोने में क्रोड न. 5130000009 वणति हुए उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारों दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके अपसंगी किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक (हुण्डो कर्ता) से प्राप्त एक हुण्डो (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारों शाखा दिल्ली-6 (हुण्डो ग्रह्या और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं. 184-आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 30-8-68 सं. 233-आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 24-10-68 सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखों में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

4(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह प्रतिरिक्त धनराशि भेजा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। जालान के विभिन्न कालों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74 दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना जालान के कालम "धन वरेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ध्यारे" में निरपवाद रूप से निदिष्ट किए गए हैं। खजाना जालान में निम्नलिखित ध्यारे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की सं. और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपवाई गई परिवर्तन की वर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) जापानी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

(घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए वह गिना गया है।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(व्याज की गणना जापानी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखों में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है)।

उत्तके परवान सी.ए.एल. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संवर्ष देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों की प्रतियों को संलग्न करते हुए खजाना जालान रुपया जमा करने का साध्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी.ए.ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी:—भारत में आयातक बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक आफ इंडिया टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलवान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी.ए.ए. एण्ड ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4(4) भारत में सम्बद्ध बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एम" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड-5 विविध शर्तें

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग की रिपोर्टें

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलवानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलवान होने वाली हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी.ए.ए. एण्ड ए. आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, यू. सी. प्रो. बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

आयातक को चाहिए कि वह इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल के आयात से संबंधित किसी ऐसी विशेष शर्त से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डालती हो।

5(3) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि आयातक और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्त साफ-साफ "भुगतान के नियमों" में अनुबंध-1 में आयातक द्वारा दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्त ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

5(4) अविषय अनुदेश

आयातों या उनके संबंध में उत्पन्न किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1984-85 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आयातों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का आयातक को तुरंत पालन करना होगा।

5(5) प्रतिक्रमण या उल्लंघन

अपयुक्त खर्चों में निर्धारित की गई शर्तों के प्रतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

5(6): अनुबंधों की सूची

अनुबंध-1 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव

अनुबंध-2 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रस्ताव

अनुबंध 1

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

संख्या "

दिनांक

सेवा में

सहायता सेवा तथा सेवा परीक्षा नियंत्रक

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,

मु. सी. प्रो. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल

परलियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:—1984-85 के लिए येन 20 मिलियन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से भारत में पत्तों पर लाने के लिए आवश्यक उपस्कर आधियों विजयुअल और सेवाओं का आयात।

महोदय

आपके निम्नलिखित अनुबंधों सहित के प्रारंभिक आयात से संबंधित उपस्कर के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ध्योरे भेजते हैं जिससे कि आप सम्बद्ध जापानी संभरक के पत्र में बैंक आफ इंडिया टोकियो को भुगतान के लिए प्रार्थना प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात सम्बंधों की संख्या दि० और मूल्य और यह कि आप तक यह बैंक है।

(ग) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष करीब पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है। इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या निविदा का निर्णय उपयुक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश।

(च) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भारतीय एजेंट के कमीशन की अनुमति (येन में)

(ज) यह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।

(झ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक

(ञ) जापानी संभरक का नाम और पता

(ट) अनुदान और संभावित तिथि जिसको संविदाओं के अंतर्गत भुगतान देखा होगा।

(ठ) माल की सुविधा पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि

(ड) बैंक आफ इंडिया टोकियो को भुगतान करने समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान क्षमता हुए)

(ड) पोतलवान अनुदेश (अनुदेश या गैर अनुदेश/बाह्यस्तरण/प्राधिक पोतलवान निर्दिष्ट कीजिए)।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(त) आयातक द्वारा वचनबद्धता:—“हम एतद्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को देय धनराशि के समतुल्य रूप की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और प्रचलित दर में सही रूप से जमा करवा देंगे माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक पत्रिका की सुविधा प्राप्त करने से पूर्व राशि गीष्ट ही जमा करवा दी जाएगी विदेशी राष्ट्रों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है उसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी।”

भवदीय,

अनुबंध 2

सं० एन

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,

टोकियो शाखा

टोकियो (जापान)

विषय: 1984-85 के लिए येन 20 मिलियन की जापानी अनुदान के अंतर्गत जापान से भारत में पत्तों पर लाने के लिए आवश्यक उपस्कर आधियों विजयुअल और सेवाओं का आयात-भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा संलग्न ध्योरे के अनुसार संबंधी को येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज संभरकों एवं बैंकों के प्रभार को भेजने और के लिए भाड़े सहित अवा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए सकारण दस्तावेज आर्थिक के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. यह भुगतान प्राधिकार पत्र के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा।

भवदीय,

(सेवा अधिकारी)

प्रति- निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक को उनके पत्र सं०

दिनांक के संदर्भ में। उनसे अनुरोध किया जाता है

कि वे बैंकों के पदकल्प्य वस्तावेजों की सुपुर्गरी लेने से पूर्व अपने बैंकों के माध्यम से निक्षेप आदि की जमा करवाने की व्यवस्था करें। यदि विशेष परिस्थितियों के बावजूद से भूल परिवहन वस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमा शुल्क प्राप्ति परियों और पतन के प्राधिकारियों से भाग की सुपुर्गरी सीधे ही प्राप्त कर ली हो, तो वहां सुपुर्गरी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवाणी चाहिए। विदेशी संभरकों द्वारा की गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही भुगतान के लिए बीजक अनुमोदित किए जाते हैं, जैसे ही धनराशि जमा करवा लेनी चाहिए। शोध ही और सही रूप से धनराशि जमा करवाने में अममय होने पर लाइसेंसिंग शर्तों में उल्लिखित कार्रवाई की जायेगी।

2. आयातक का बैंक उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आक-इंडिया, टोकियो, ब्रांच से वस्तावेज प्राप्त करने पर आपसी संभरकों को येन भुगतान के बराबर रकमा जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को सुझाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक की अवधि करने की तिथि तक सरकार के लेखों में तुल्य रूपया जमा करने की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 31-आई टी सी (पी एन)/83 दिनांक 10-8-83 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18% की दर से ब्याज भी सरकारी लेखों में जमा करना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए देय होगा अर्थात् वह तिथि जिसकी विदेशी संभरक की भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिस दिन सरकारी लेखों में रकमा निक्षेप किया जाता है। (यदि इस दर में कोई परिवर्तन होता तो इसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी)।

वस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कराई जानी है

कालान के दाएं कोने के कोड नं० 5130000009 बणित हुए ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आक इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आक इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीय बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आक इंडिया, तमिळुनाडु शाखा, दिल्ली 6 (अन्वेषित और आवाता) के नाम में और उसकी देय दर्शनी टुण्डों के माध्यम से करने चाहिए। इस संबंध में आपका इस सार्वजनिक सूचना सं० 233-आई टी सी (पी एन)/60 दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 13-10-76 की शर्तों को और ध्यान दिया जाना है। लेखकों के लिए धनराशि जमा की जायेगी वह "के" डिपॉजिट एण्ड एक्वालिटी 843 सिविल डिपॉजिट डिपॉजिट—फार परमिज एटसेट्टा एक्वा परमिजिज ग्रान्ट एंड फ्राम वि गवर्नमेंट आक जापान फार 1984-85 है और विस्तृत लेखा संर्षक नैशनल काउंसिल आक साइंस म्यूजियम कलकता के एकसपर्ट को प्रशिक्षण देने के लिए आडियो विजुअल और उपस्कर/सेवाओं को एक के लिए येन 20 मिलियन अतुदाम सहमत।

जिस मामले में तुल्य रूपया निक्षेप बैंक आक इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आक इंडिया तमिळुनाडु शाखा में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के अनुसार नक़्क जमा किया जाता है उनमें कालान की मूल रूप में एक प्रतिनिधि बैंक आक इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पत्र पर भेजी जाएगी:-

विश्व मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग)

पहली मंजिल यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,

संसाधनार्ण, नई दिल्ली-110001

जिस मामले में तुल्य रूपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित शर्तों टुण्डों द्वारा प्रेषित करना है उनकी सूचना उपर्युक्त पत्र पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की सुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रूपए का पूरा ब्योरा हम विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंक के बैंकों सहित यदि कोई हो, बैंकिंग खातों और बैंक आक इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खातों इंडियन बैंक और बैंक आक इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव (टी ए) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 46-ITC(PN)/84

New Delhi, the 18th August, 1984

Subject : Licensing conditions for import of Audio-Visual equipment and services necessary for the transportation of equipment to ports in India from Japan by the National Council of Science Museums, Calcutta under Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen twenty million.

File No. IPC/23(6)/84.—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of Yen 20 million of Audio-Visual equipment from Japan by the National Council of Science Museums, Calcutta, as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No. 46-ITC(PN)/84, dated the 18th August, 1984

Licensing Conditions for import of Audio Visual equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen twenty million (Yen 20,000,000).

Section I. General Conditions :

I. (i) The Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen 20 million (C&F) is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for import of audio visual equipment and services necessary for the transportation thereof to ports in India, by the National Council of Science Museums, Calcutta.

I (ii) The import licence should be issued for an amount not exceeding Yen 22 million (CIF) in favour of the importer, and should bear the superscription "Yen 20 million Japanese Grant Aid for 1984-85". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN".

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels, payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will therefore be charged to the licence.

I (iv) The equipment should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I (v) The import licence will be issued on CIF basis with validity upto 31-3-1985.

I (vi) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

“delivery to be completed by 15-3-1985”

I (vii) The contract value (C&F basis only) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency.

The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I (viii) The purchase contract should be entered into only with the Japanese nationals or Japanese juridical persons controlled by Japanese nationals.

Section II.—The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 11th May, 1984 between the Government of India and Government of Japan concerning the Grant Aid of Yen 20 million for 1984-85 and will be subject to the approval of both the Governments.

II (ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1984-85.

II (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II (iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III. Contract Approval by Governments of India and Japan.

III (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (I.A.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III (ii) The Ministry of Finance (DEA), Japan Section will arrange to send one copy of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen 20 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department

of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the [redacted] who will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

III (v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittance to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV. Responsibility for rupee deposit

IV (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76-dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited in to the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the custom authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further IAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&F so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843 Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan"—for 1984-85 Grant for purchase of the audio visual equipment/services for the purpose of training the experts of the National Council of Science Museums, Calcutta.

IV (ii) The amount referred to above should be deposited in the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, indicating Code No. 5130-09 on the right hand corner of the Challan or in the Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawer and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

IV (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans.

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
 - (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
 - (c) Date of payment to the Japanese supplier.
 - (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.
 - (e) Total amount deposited.
- (Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V : Miscellaneous provisions

V (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid.—The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made thereagainst and about the balance left, to the Controller of Air Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect suppliers in carrying out the transaction.

V (ii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly set out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V. (iv) Future Instructions.—The importer shall comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1984-85 from Japan.

V (v) Breach or violation.—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V (vi) List of Annexures :

Annexure I :—Request for issue of A/P

Annexure II :—Form of A/P

Annexure-I

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject : Import of audio visual equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 20 million for 1984-85.

Sir,

In connection with the import of above mentioned equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese Supplier concerned :—

- (a) Name and address of Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Account of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name and date of the contract with Japanese Suppliers.
- (j) Name and address of the Japanese Supplier and attach an eligibility certificate (in duplicate).
- (k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/partshipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of Importers bank in India.
- (p) Undertaking by the importer.—"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee

equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the suppliers."

Yours faithfully,

Annexure-II

No. F.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs

New Delhi.....

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject : Import of audio visual equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid of Yen 20 million for 1984-85. Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated—entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen— to M/s.—as per details given in the appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including charges for handling documents and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any payable to you by the importer, will be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendment to this A/P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto—.

Yours faithfully,

Accounts Officer.

Copy forwarded to :—

1. Importer— with reference to their letter No.—dated—.

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign Nationals, the deposits should be made as soon as

the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may result in action as mentioned in the Licensing conditions.

2. Importer's Banker— They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @12% per annum for the first thirty days and at the rate of 18 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notices No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan, or in the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of account to be credited is 'K-Deposits and Advances-843 Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from Government of Japan for 1984-85 under detailed head Y' 20 million grant aid for purchase of the audio visual training equipment/services for the purpose of training the experts of the National Council of Science Museums, Calcutta.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audi, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

3. Embassy of India, Tokyo.

4. The Under Secretary (IA), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

()

Accounts Officer